MALUKA IAS

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

CLASS NOTES

MALUKA IAS

INDEX

S.NO.	TOPICS	PAGE NO.
1.	India-Bangladesh Relations: Fraternal Friendship	1-6
2.	India and Bhutan	7-8
3.	India and Nepal	9-14
4.	India Sri Lanka	15-18
5.	India Maldives	19-31
6.	India and China	32-44
7.	India and Pakistan	45-56
8.	India and Afghanistan	57-59
9.	India and the United States of America.	60-73
10.	India and Russia	74-80
11.	India and the European Union	81-94
12.	India and west Asia	95-111
13.	India and central Asia	112-118
14.	India and South East Asia	119-133
15.	India and Africa	134-139
16.	India and Latin America	140-145
17.	India and the Indo-Pacific	146-154
18.	India and the Indian Ocean	155-159
19.	India's Relations: Evolution of India's Foreign Policy	160-175
20.	Key Issues in International Relations	176-199
21.	the diaspora: Indian's Around the World	200-208
22.	Organisations, Groupings and Institutions in International Relations	209-231

भारत-बांग्लादेश संबंध: भाईचारे की दोस्ती

पार्श्वभूमि

• भारत और बांग्लादेश भूमि और समुद्री सीमाओं, सीमाओं के पार जातीय संबंधों के साथ-साथ सीमा पार नदियों को साझा करते हैं।
भाषा, संस्कृति और विकास पथ में समानता संबंधों को खास बनाती है
• भौगोलिक स्थान एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों के लिए अपने कनेक्टिविटी लिंक और अर्थव्यवस्थाओं को और विकसित करने का अवसर प्रदान करते हैं।
• भारत ने 1971 में मुक्ति वाहिनी और अवामी लीग के नेतृत्व, विशेष रूप से शेख मुजीबुर रहमान को नैतिक, भौतिक, सैन्य और राजनयिक समर्थन प्रदान करके बांग्लादेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
• बांग्लादेश को एक अलग और स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने वाला भारत पहला देश था।
• 1972 की शांति और मित्रता की भारत बांग्लादेश संधि ने दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों की नींव रखी

विकास

• आरंभिक वर्षों की सौहार्द के बावजूद संबंधों में खटास आई, खासकर सैन्य तख्तापलट और शेख मुजीबुर रहमान की हत्या और वर्ष 1975 में सैन्य शासक जिया उर रहमान के उदय के बाद से।
• बांग्लादेश 1975 से 1990 तक सैन्य या अर्ध सैन्य शासन के अधीन रहा।
• इस अवधि में, अधिकांश भाग के लिए, संबंधों में कुछ समय की बढ़ी हुई उम्मीदें और लंबी अवधि की शीतलता थी।
• बांग्लादेश नेशनलिस्ट पैरी (बीएनपी) की बेगम खालिदा जिया 1991 में प्रधान मंत्री बनीं।

1996 में शेख हसीना के नेतृत्व में अवामी लीग सत्ता में आई। 2001 में वह बीएनपी और खालिदा जिया से हार गईं। 2008 शेख हसीना के नेतृत्व में अवामी लीग की जीत देखी
• भारत-बांग्लादेश संबंधों में सबसे खराब दौरों में से एक 2001 और 2006 के बीच था।
इस समय के दौरान केवल मामूली प्रोटोकॉल या समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे और प्रशिक्षण के लिए सीमा पार करने वाले अन्य संगठनों के अलावा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम और नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के साथ पूर्वोत्तर में उग्रवाद गतिविधियों में वृद्धि हुई थी।
• 2009 के बाद से, जैसे-जैसे सीमा पार मुद्दों का समाधान किया गया, द्विपक्षीय संबंधों में सुधार हुआ और कुछ प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति हुई।
• हाल के वर्षों में नई दिल्ली में विभिन्न सरकारों के तहत इन संबंधों में उल्लेखनीय बदलाव आया है।

हाल के शीर्ष स्तर के दौरे

• बांग्लादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना ने अप्रैल 2017 में भारत का दौरा किया।
दोनों देशों ने 22 समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
• प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2015 में बांग्लादेश का दौरा किया
• प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने 2011 में बांग्लादेश का दौरा किया

नदी का पानी

• भारत और बांग्लादेश 54 साझा नदियाँ साझा करते हैं: गंगा और ब्रह्मपुत्र उनमें से प्रमुख हैं।
बांग्लादेश एक निचला तटवर्ती राज्य है।
• साझा नदी प्रणालियों का सर्वेक्षण करने के लिए 1972 में संयुक्त नदी जल आयोग का गठन किया गया था।
• हुगली नदी को प्रवाहित करने और कोलकाता बंदरगाह को चालू रखने के लिए गंगा के पानी का उपयोग करने के लिए भारत द्वारा 1975 में निर्मित फर्रक्का बैराज विवाद का विषय बन गया।
जनरल जिया के नेतृत्व में बांग्लादेश ने भारत का सामना किया और इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की।

• अंततः 1977 में जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत में एक नई सरकार के साथ एक समझौता हुआ, जिसे फरक्का समझौते के रूप में जाना जाता है।

• गंगा नदी के जल के बंटवारे के लिए 1996 में गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे (जनवरी 1-मई 31)।
• तीस्ता नदी पर, 1984 में जल बंटवारे के लिए दोनों पक्षों द्वारा एक अंतरिम समझौता किया गया था।
हालांकि, एक अंतिम समझौता मायावी रहा है। पश्चिम बंगाल की सरकार पश्चिम बंगाल की पानी की जरूरतों और मांगों के प्रति अन्यायपूर्ण और असंवेदनशील माने जाने वाले ऐसे किसी भी समझौते का विरोध करती है।

तीस्ता विवाद

• ऐतिहासिक रूप से, नदी पर विवादों की जड़ सीमा आयोग (बीसी) की रिपोर्ट में स्थित हो सकती है, जिसे 1947 में सर सिरिल रैडक्लिफ के तहत पश्चिम बंगाल (भारत) और पूर्वी बंगाल के बीच सीमा रेखा का सीमांकन करने के लिए स्थापित किया गया था। पाकिस्तान, फिर 1971 से बांग्लादेश)।
पाकिस्तान के हिस्से के रूप में पूर्वी बंगाल के दिनों में, भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच पानी के मुद्दों पर कोई गंभीर बातचीत नहीं हुई।
1972 में, भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की स्थापना की गई थी।

• तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से होकर बहती है। भारत नदी के पानी के 55 प्रतिशत हिस्से का दावा करता है।
• नदी सिंचाई और मछली पकड़ने के लिए बांग्लादेश की चौथी सबसे बड़ी सीमा पार नदी है।
तीस्ता की बाढ़ का मैदान बांग्लादेश में 2,750 वर्ग किमी में फैला है। नदी के जलग्रहण क्षेत्र में से - भूमि का एक क्षेत्र जहाँ पानी इकट्ठा होता है - 83 प्रतिशत भारत में और 17 प्रतिशत बांग्लादेश में है।
ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने कहा कि इसका मतलब है कि बांग्लादेश के पांच जिलों में एक लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि भारत में तीस्ता के पानी की निकासी से बुरी तरह प्रभावित है।
बांग्लादेश के इन पांच जिलों को सूखे के मौसम में भारी कमी का सामना करना पड़ता है।

• 1983 में, तीस्ता से पानी के बंटवारे पर एक तदर्थ व्यवस्था की गई, जिसके अनुसार बांग्लादेश को 36% और भारत को 39% पानी मिला, जबकि शेष 25% पानी का आवंटन नहीं हुआ।
• गंगा जल संधि के बाद, अन्य नदियों के अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की एक संयुक्त समिति का गठन किया गया था।
समिति ने तीस्ता को महत्व दिया। 2000 में, बांग्लादेश ने तीस्ता पर अपना मसौदा प्रस्तुत किया।
अंतिम मसौदा 2010 में भारत और बांग्लादेश द्वारा स्वीकार किया गया था।

2011 में, तत्कालीन भारतीय प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह की ढाका यात्रा के दौरान, दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व के बीच तीस्ता जल साझा करने के एक नए सूत्र पर सहमति हुई थी।
• 2011 की अंतरिम डील - जो 15 साल तक चलने वाली थी - ने भारत को तीस्ता का 42.5 प्रतिशत पानी दिया और बांग्लादेश को 37.5 प्रतिशत दिया।
• पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस सौदे का विरोध किया, इसलिए इसे स्थगित कर दिया गया और अहस्ताक्षरित बना रहा।
दरअसल, वह 2011 में उस सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह के साथ बांग्लादेश जाने वाली थीं, लेकिन उन्होंने यात्रा रद्द कर दी।

• पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अतीत में बांग्लादेश के तर्क का विरोध करते हुए कहा कि तीस्ता का पानी भारत पहले से ही बांग्लादेश को देता है।
"जब हमें अपने कोलकाता बंदरगाह को बनाए रखने और किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक निश्चित मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, तो तीस्ता और फरक्का बैराज से पानी बांग्लादेश को छोड़ दिया जाता है और राज्य के हितों का त्याग करता है"
उसने 2013 में कहा था।
• तीस्ता पर जलविद्युत संघर्ष का एक अन्य बिंदु है।
नदी पर कम से कम 26 परियोजनाएं ज्यादातर सिक्किम में हैं, जिनका लक्ष्य कुछ 50,000 मेगावाट उत्पादन करना है।

• ममता बनर्जी ने अन्य नदियों के पानी को बांटने का प्रस्ताव रखा है।
जैसा कि उत्तर बंगाल पूरी तरह से तीस्ता पर निर्भर है, उसने कहा, भारत और बांग्लादेश की सीमा के करीब तोरसा और मनशई जैसी नदियाँ अच्छे विकल्प हैं।
टोरसा, वास्तव में, बांग्लादेश की पद्मा नदी के साथ जुड़ा हुआ है।
पश्चिम बंगाल के सीएम ने प्रस्ताव दिया कि दोनों देशों ने तोरसा से बहने वाले पानी के स्तर और साझा किए जा सकने वाले पानी की मात्रा का पता लगाने के लिए एक आयोग का गठन किया।

सीमा मुद्दा

• भारत और बांग्लादेश का हिस्सा 4096.7 किमी है। सीमा की, जो सबसे लंबी भूमि सीमा है जिसे भारत अपने किसी भी पड़ोसी के साथ साझा करता है।

• 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट (एलबीए) के प्रभावी होने से पहले, कई एक्सक्लेव और एन्क्लेव के कारण सीमा विवादास्पद थी।
• बांग्लादेश को पश्चिम बंगाल में अपने परिक्षेत्रों तक पहुंच की अनुमति देने के लिए, भारत सरकार ने 1974 में भूमि के एक छोटे गलियारे (तीन बीघा कॉरिडोर) को पट्टे पर देने पर सहमति व्यक्त की थी।
हालाँकि, इसे भारत के भीतर मजबूत घरेलू विरोध का सामना करना पड़ा और इस मामले को अंततः 1982 में ही सुलझा लिया गया।
इसने समझौते के कार्यान्वयन में देरी पर अनावश्यक घर्षण उत्पन्न किया

सीमाएँ और सीमाएँ: प्रमुख समझौते

• सीमा पार अवैध गतिविधियों और अपराधों पर अधिक प्रभावी नियंत्रण के लिए दोनों सीमा सुरक्षा बलों के प्रयासों के साथ-साथ शांति और शांति बनाए रखने के लिए 2011 में एक समन्वित सीमा प्रबंधन योजना (सीबीएमपी) पर हस्ताक्षर किए गए थे।
भारत-बांग्लादेश सीमा।
• भूमि सीमा समझौता (एलबीए) 2015 में लागू किया गया था।
• भारत सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर 3326.14 किमी की सीमा तक कांटेदार तार की बाड़ लगाने की मंजूरी दी है।
इसमें से मार्च 2017 तक 2731 किलोमीटर तक बाड़ लगाने का काम पूरा कर लिया गया है।
• 7 जुलाई 2014 को यूएनसीएलओएस अवार्ड के अनुसार भारत और बांग्लादेश के बीच समुद्री सीमा मध्यस्थता के निपटारे ने बंगाल की खाड़ी के इस हिस्से के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया और इसे दोनों देशों के लिए फायदेमंद माना जाता है।

एलबीए

भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता (LBA), पहली बार 1974 में हस्ताक्षरित किया गया था। इस समझौते के लिए एक प्रोटोकॉल 2011 में हस्ताक्षरित किया गया था।

तीन बकाया मुद्दे थे:

o लगभग 6.1 किमी . की एक गैर-सीमांकित भूमि सीमा
o परिक्षेत्रों का आदान-प्रदान
ओ अनसुलझे प्रतिकूल कब्जा

• भारतीय संसद द्वारा प्रासंगिक अधिनियम (100वां संशोधन अधिनियम) के पारित होने और उसी वर्ष उपकरणों के आदान-प्रदान के साथ, समझौता 2015 में लागू किया गया था।
• इस कदम ने न केवल सीमाओं के अंतिम निपटान के लिए सभी बाधाओं को दूर किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी), जिसे रेडक्लिफ रेखा के रूप में भी जाना जाता है, को फिर से खींचकर एन्क्लेव के आदान-प्रदान और प्रतिकूल कब्जे के विलय का मार्ग सुनिश्चित किया।
• भारत ने 17,160.63 एकड़ के कुल क्षेत्रफल वाले 111 एन्क्लेव बांग्लादेश को हस्तांतरित किए, जबकि बांग्लादेश ने 7,110.02 एकड़ क्षेत्र के 51 एन्क्लेव भारत को हस्तांतरित किए।
• जहां तक प्रतिकूल कब्जे का सवाल है, भारत ने 2777.038 एकड़ भूमि प्राप्त की और 2267.682 एकड़ बांग्लादेश को हस्तांतरित की।

• इस प्रकार, 2015 एलबीए तीन क्षेत्रों में गैर-सीमांकित भूमि सीमा-लगभग 6.1-किमी लंबी-से उत्पन्न अनसुलझे मुद्दों को लागू करता है, अर्थात। दाइखाता-56 (पश्चिम बंगाल), मुहुरी नदी-बेलोनिया (त्रिपुरा) और लथिला-दुमबारी (असम);

o परिक्षेत्रों का आदान-प्रदान; तथा
o प्रतिकूल संपत्तियां, जिन्हें पहली बार 2011 के प्रोटोकॉल में संबोधित किया गया था।

• भारत में बांग्लादेशी एन्क्लेव के लगभग 14,000 निवासियों ने एलबीए के तहत उन्हें दिए गए विकल्प के अनुसार रहने और नागरिक बनने का फैसला किया है। लगभग 37,000 में से बांग्लादेश में भारतीय परिक्षेत्रों के 971 निवासियों ने भारतीय नागरिकता का विकल्प चुना।

समुद्री सीमा पुरस्कार

• 7 जुलाई 2014 को हेग स्थित परमानेंट कोर्ट ऑफ एट्रिब्यूशन (पीसीए) के एक ऐतिहासिक फैसले ने बांग्लादेश को 19,467 वर्ग किमी का क्षेत्र दिया, जो भारत के साथ बंगाल की खाड़ी में विवादित समुद्री सीमा के 25,602 वर्ग किमी के कुल क्षेत्रफल का चार-पांचवां हिस्सा है। .
• संयुक्त राष्ट्र ट्रिब्यूनल के पुरस्कार ने स्पष्ट रूप से भारत और बांग्लादेश के बीच प्रादेशिक समुद्र, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) और महाद्वीपीय शेल्फ में 200 समुद्री मील (एनएम) के भीतर और परे समुद्री सीमा रेखा के पाठ्यक्रम को चित्रित किया।
• अब, बांग्लादेश की समुद्री सीमा को 118,813 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है जिसमें 12 एनएम प्रादेशिक समुद्र और 200 एनएम तक ऊंचे समुद्रों में एक ईईजेड शामिल है।
इसके अलावा, सत्तारूढ़ ने चटगांव तट को आधार रेखा के रूप में लेते हुए, उच्च समुद्र में 345 एनएम तक फैले महाद्वीपीय शेल्फ में पानी के नीचे संसाधनों के बांग्लादेश के संप्रभु अधिकारों को स्वीकार किया।

• इस फैसले को दोनों देशों द्वारा व्यापक रूप से मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने के सकारात्मक विकास के रूप में स्वीकार किया गया है
• भारत भी इस फैसले से खुश है और इसे विभिन्न कारणों से एक कूटनीतिक सफलता मानता है।
अन्य लाभों के अलावा, फैसले ने न्यू मूर द्वीप पर भारत की संप्रभुता को मान्यता दी है और लगभग 6000 वर्ग किमी के विवादित क्षेत्र को सम्मानित किया है जहां द्वीप कभी अस्तित्व में था।

समुद्री सीमा पुरस्कार का महत्व

हिंद महासागर क्षेत्र और दक्षिण एशियाई उप-क्षेत्र के भू-रणनीतिक/राजनीतिक महत्व को देखते हुए यह पुरस्कार महत्वपूर्ण है।
इसके अलावा, इस पुरस्कार के न केवल भारत और बांग्लादेश के लिए बल्कि पूरे बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के लिए व्यापक सुरक्षा और आर्थिक निहितार्थ हैं।
• फैसला रणनीतिक स्थापित करने में योगदान देगा
खाड़ी में सीमा साझा करने वाले देशों के बीच साझेदारी।
इस पुरस्कार से बिम्सटेक जैसे उभरते बहुपक्षीय मंच पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
• इस फैसले को दोनों देशों द्वारा व्यापक रूप से मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने के सकारात्मक विकास के रूप में स्वीकार किया गया है, विशेष रूप से अधिक हिंद महासागर क्षेत्र और दक्षिण एशियाई उप-क्षेत्र के भू-रणनीतिक/राजनीतिक महत्व को देखते हुए।
• दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा को स्पष्ट रूप से चित्रित करके, इस फैसले से क्षेत्र में तटीय और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।

• इसने खाड़ी में तेल और गैस की खोज के लिए द्वार खोल दिया - विशाल ऊर्जा भंडार की साइट।
2006 में भारत में प्राकृतिक गैस की खोज एक नाले में हुई जो विवादित क्षेत्र के भीतर हरिभंगा नदी के मुहाने से लगभग 50 किमी दक्षिण में स्थित है।
• मात्स्यिकी संसाधनों का विकास एक और संभावना है।
• इस पुरस्कार से क्षेत्रीय एकीकरण और बिम्सटेक जैसे उभरते बहुपक्षीय मंच पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि भारत पहले ही श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड के साथ अपनी समुद्री सीमाओं को तय कर चुका है।

आर्थिक सहयोग और व्यापार

• भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले एक दशक में तेजी से बढ़ा है।
पिछले पांच वर्षों में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार में 17% से अधिक की वृद्धि हुई है। जुलाई 2016-मार्च 2017 की अवधि में बांग्लादेश को भारत का निर्यात 4489.30 मिलियन अमेरिकी डॉलर और वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान बांग्लादेश से आयात 672.40 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
• अनुमान है कि व्यापार क्षमता वर्तमान स्तर से कम से कम चार गुना है।

• लाइन ऑफ क्रेडिट:

हाल के वर्ष में भारत ने बांग्लादेश को कई परियोजनाओं के लिए 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है, जिसमें रेलवे अवसंरचना, ब्रॉड गेज माइक्रोप्रोसेसर-आधारित इंजनों और यात्री डिब्बों की आपूर्ति, बसों की खरीद और ड्रेजिंग परियोजनाएं शामिल हैं।
यह भारत द्वारा अब तक किसी भी अन्य देश को दिए गए ऋण की सबसे बड़ी मात्रा है और यह अत्यधिक रियायती ब्याज दर पर आता है।

• शुल्क-मुक्त पहुंच के बावजूद, बांग्लादेशी निर्यातकों को नौकरशाही और सीमा शुल्क बाधाओं के रूप में उच्च गैर-टैरिफ बाधाओं का सामना करना पड़ता है, मैन्युअल मंजूरी के कारण देरी, वीजा समस्याएं, बैंकिंग सेवाओं की कमी और सीमा पर गोदाम की सुविधा।
सीमा पार व्यापार की लागत काफी अधिक है।
• 'बॉर्डर हाट', या भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाज़ार (वर्तमान में ऐसे चार हाट काम कर रहे हैं), सीमाओं पर कानूनी कारोबार बढ़ाने के लिए एक सफल समाधान थे।
हाल ही में, बांग्लादेश और भारत अपनी सीमाओं के साथ छह और हाट स्थापित करने पर सहमत हुए हैं।

ऊर्जा

• बिजली: भारत से बांग्लादेश तक सरकार से सरकार का बिजली व्यापार 1,300 मेगावाट है।
• भारत की सरकारी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) बांग्लादेश में रामपाल कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र का निर्माण कर रही है।
• निजी क्षेत्र में, रिलायंस पावर ने बांग्लादेश में 750 मेगावाट एलएनजी आधारित बिजली संयंत्र और एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने की मंजूरी हासिल कर ली है, जिससे 1.3 अरब डॉलर के निवेश का मार्ग प्रशस्त हो गया है, और अदानी समूह बांग्लादेश को 3,000 मेगावाट बिजली बेचने के लिए तैयार है।
• संपर्क: सड़क, रेल, नदियां, समुद्र, पारेषण लाइन, पेट्रोलियम पाइपलाइन और डिजिटल लिंक पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो भारत को बांग्लादेश के माध्यम से पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंच प्रदान करेगा।

कनेक्टिविटी

• दो ट्रेन सेवाएं, मैत्री और बंधन, कोलकाता और ढाका के बीच चलती हैं।
• ढाका के रास्ते नई कोलकाता-ढाका-अगरतला बस सेवा 2016 में शुरू की गई थी।
• ढाका के रास्ते कोलकाता से अगरतला तक ट्रेनें चलाने की योजना है, यह परियोजना 2019 में पूरी की जाएगी। अखौरा-अगरतला खंड के पूरा होने पर त्रिपुरा और कोलकाता के बीच की रेलवे दूरी 1,000 किमी से अधिक कम हो जाएगी।
• दोनों पक्ष पंचगढ़ (बांग्लादेश) से सिलीगुड़ी (भारत) के बीच एक नया रेल लिंक स्थापित करने के बांग्लादेश के अनुरोध की जांच करने पर सहमत हुए।
• बांग्लादेश-भारत तटीय नौवहन का संचालन मार्च 2016 में शुरू हुआ।
• 2017 में बांग्लादेश ने भारतीय जहाजों को चटगांव बंदरगाह पर डॉक करने की अनुमति दी, 40 साल बाद पहली बार। पेरा पोर्ट को विकसित करने में भारतीय कंपनियों की दिलचस्पी है।
• भारतीय सामान ढोने वाले ट्रक 19 जून 2016 को बांग्लादेश के आशुगंज बंदरगाह से त्रिपुरा पहुंचे, जिसने ट्रांसशिपमेंट के लंबे समय से पोषित विचार को हकीकत में बदल दिया।
• ग्रिड कनेक्टिविटी: बांग्लादेश पहले से ही भारतीय ग्रिड से 600 मेगावाट प्राप्त कर रहा है, और 500 मेगावाट भीरामारा-बहरामपुर इंटर-कनेक्शन के माध्यम से जोड़ा जाना है।